

घटना घटना

सत्य के साथ... जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर, वर्ष 22, अंक - 108 - मंगलवार 17 - फरवरी 2026, पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रुपये RNI Reg.No. - CHHIN/2004/15050, डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

राजस्थान में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका... 8 लोग जिंदा जले

4 गंभीर झुलसे, पॉलीथीन में ले जाने पड़े शव, मैनेजर हिरासत में, फैक्ट्री सीज

भिवाड़ी, 16 फरवरी 2026। राजस्थान के भिवाड़ी की केमिकल फैक्ट्री में अचानक तेज धमाका हुआ। इसमें 8 मजदूर जिंदा जल गए, जबकि 4 गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें दिल्ली एम्स रेफर किया गया है। शव बुरी तरह जल गए थे। कई शवों के कंकाल भर बचे थे। बाँड़ी पाटर्स के टुकड़े बिखरे मिले। रेस्क्यू टीम ने इन टुकड़ों को पॉलीथीन में इकट्ठा किया। हदसा खुशखेड़ा कारोली इंडस्ट्रियल परिया में सोमवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे हुआ। फैक्ट्री मैनेजर अभिनंदन को हिरासत में लेकर पुलिस पछताछ कर रही है। फैक्ट्री को सीज कर दिया है। तीन मृतकों की पहचान बिहार के मोतिहारी जिले के मिंटू नितेश और सुजान के रूप में हुई है। अन्य मृतकों की पहचान के लिए उनके परिजनों का डीएनए सैपल लिया जाएगा। इस फैक्ट्री में अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे। मौके से बारूद, पटाखे और पैकिंग के डिब्बे मिले हैं। घटना के समय करीब 25 मजदूर काम कर रहे थे। कलेक्टर अतिका शुक्ला ने कहा- देखकर लग रहा है कि छोटा एक्सप्लोसिव मटेरियल था। गैस रिसाव नहीं था। एडीएम सुमिता मिश्रा के अनुसार, फैक्ट्री मालिक का नाम राजेंद्र है। उन्होंने किसी तिवाही को यह फैक्ट्री लीज पर दी थी। दोनों से संपर्क नहीं हो पाया है।



सभी फैक्ट्रियों की जांच होगी

खैरथल-तिजारा जिला कलेक्टर अतिका शुक्ला ने 7 दिन में सभी फैक्ट्रियों और औद्योगिक इकाइयों की जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा- जांच में यह देखा जाएगा कि औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा के नियम सही तरह से लागू हो रहे हैं या नहीं। इस दौरान वहां चल रही गतिविधियों, आग से बचाव के इंतजाम, जरूरी सरकारी अनुमति और मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था को बारीकी से देखा जाएगा।

फैक्ट्री मैनेजर को पुलिस ने थाने बुलाकर हिरासत में लिया

पुलिस सुबह से फैक्ट्री मालिक और मैनेजर से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। काफी कोशिश के बाद फैक्ट्री के मैनेजर अभिनंदन से फोन पर बात हो पाई। अब पुलिस ने उसे थाने बुलाने के बाद हिरासत में ले लिया है। पुलिस फैक्ट्री मैनेजर से पछताछ कर रही है।



तीन मृतकों की पहचान हुई

8 मृतकों में से 3 की पहचान हो गई है। ये तीनों मिंटू नितेश और सुजान बिहार के मोतिहारी जिले के रहने वाले थे। इसके अलावा 4 मजदूरों अनूप कुमार, जनुन, विवेक कुमार और मनु को एम्स रेफर किया गया है। बाकी शव इतनी बुरी तरह जल गए हैं कि पहचान डीएनए जांच के बाद ही संभव हो पाएगी।

प्रधानमंत्री ने राजस्थान के भिवाड़ी में आग लगने की घटना पर दुःख
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को राजस्थान के भिवाड़ी में आग लगने की घटना पर दुःख जताया। उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दुःख व्यक्त करते हुए लिखा कि राजस्थान के भिवाड़ी में आग लगने की घटना अत्यंत दुःख है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उल्लेखनीय है कि राजस्थान के भिवाड़ी के खुशखेड़ा कारोली औद्योगिक क्षेत्र स्थित प्लांट संस्था जी1/118वीं में सोमवार सुबह अग्निकांड की घटना सामने आई, जहां संचालित एक निजी औद्योगिक इकाई में अचानक आग लग गई।

सीएम भजनलाल ने कहा... राहत, बचाव कार्य के निर्देश दिए गए...
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा... जिला प्रशासन को राहत व बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। भिवाड़ी के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री में आग लगने से हुई जनहानि का समाचार अत्यंत दुःख है। जिला प्रशासन को राहत व बचाव कार्य के लिए निर्देशित किया है। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ।...

पीएम मोदी ने एआई इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन किया

300 से ज्यादा कंपनियां दिखा रही एडवांस गैजेट्स

नई दिल्ली, 16 फरवरी 2026। भारत में दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इवेंट में एक 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसका औपचारिक उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने इवेंट में शामिल हुए स्टार्टअप के प्रबेलियंस में जाकर उनके इनोवेशंस की जानकारी ली। ये इवेंट 20 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में चलेगा। समिट के साथ-साथ 'इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026' का भी आयोजन किया जा रहा है। यहां दुनियाभर की कंपनियां अपने लेटेस्ट एआई सॉल्यूशंस को दुनिया के सामने पेश करेंगीं। यहां आम लोग देख सकेंगे कि एआई असल जिंदगी में कैसे काम करता है और भविष्य में एआई से खेती, सेहत और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में क्या बदलाव लाने वाला है।

पीएम मोदी बोले... दुनियाभर से आए लोगों का स्वागत
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया 'एआई इम्पैक्ट समिट' शुरू हो रही है। मैं इस समिट में हिस्सा लेने आए दुनिया भर के नेताओं, बड़े बिजनेसमैन, इनोवेटर्स, पॉलिस्सी बनाने वालों, रिसर्चर्स



और टेक्नोलॉजी के जानकारों का दिल से स्वागत करता हूँ। इस समिट की थीम 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' यानी 'सबका भला और सबकी खुशी' है। यह इंसानियत की तरक्की के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल करने के हमारे साझा संकल्प को दिखाती है। ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन ने कहा कि अमेरिका के बाद भारत चैटजीपीटी का दूसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता आधार है। अल्टमैन ने यह भी कहा कि अन्य किसी भी देश की तुलना में भारत में चैटजीपीटी के छत्र उपयोगकर्ताओं की संख्या सबसे अधिक है।

दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस... नई न्याय संहिता से बढ़ेगी दोषसिद्धि : शाह

नई दिल्ली, 16 फरवरी 2026। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि नई न्याय संहिताओं के पूरी तरह लागू होने से देश में कानून-व्यवस्था की स्थिति में बड़ा सुधार होगा और दोष सिद्धि दर 80 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। शाह ने दिल्ली पुलिस के 79वें स्थापना दिवस पर आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की आंतरिक सुरक्षा ने पिछले 12 वर्षों में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। कश्मीर (धारा 370 हटाने के बाद), पूर्वोत्तर और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा के आंकड़े 80 प्रतिशत तक घटे हैं और इस साल 31 मार्च तक देश को पूरी तरह नक्सल करता हूँ। इस समिट की थीम 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' यानी 'सबका भला और सबकी खुशी' है। यह इंसानियत की तरक्की के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल करने के हमारे साझा संकल्प को दिखाती है। ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन ने कहा कि अमेरिका के बाद भारत चैटजीपीटी का दूसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता आधार है। अल्टमैन ने यह भी कहा कि अन्य किसी भी देश की तुलना में भारत में चैटजीपीटी के छत्र उपयोगकर्ताओं की संख्या सबसे अधिक है।



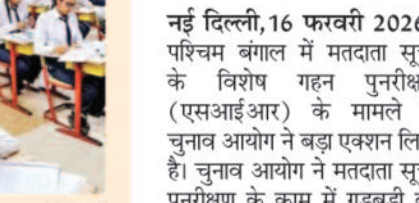
सम्पन्न, जन सुरक्षा में निभाई जा रही भूमिका और सेवा की सराहना की। कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस की बेस्ट मार्चिंग टुकड़ी, स्वाट टीम, डॉग स्क्वाड, बॉट यूनिट, मोटरसाइकिल राइडर्स और पीसीआर यूनिट्स ने मार्च पास्ट कर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। इस दौरान गृहमंत्री ने दिल्ली पुलिस की सी2आई इकाइयों और 10,000 कैमरों का नेटवर्क शामिल है, जिनमें से 2100 कैमरे पहले ही लाइव हो चुके हैं। इसके अलावा पुलिस फैमिलीज वेलफेयर सोसाइटी के स्टर्लक का लोकार्पण भी किया गया। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली पुलिस का दायित्व पूरे

देश के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली केवल एक शहर नहीं बल्कि लोकतंत्र की धड़कन और देश की अस्मिता का केंद्र है। यह राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और निवास, राष्ट्रीय पर्वों और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस पर है।

उन्हें गर्व है कि दिल्ली पुलिस ने हमेशा अपनी जिम्मेदारी को प्रखरता और सफलता के साथ निभाया है। उन्होंने कहा कि लगभग पौने चार सौ करोड़ रुपये की लागत से स्पेशल सेल का इंटीग्रेटेड हेड क्वार्टर बनाया जा रहा है, जो देश का सबसे आधुनिक केंद्र होगा। इसमें अत्याधुनिक इंडोर फायरिंग रेंज, वॉर रूम, साइबर लैब, प्रशिक्षण हॉल और आधुनिक उपकरण होंगे। यह केंद्र नारकोटिक्स और आतंकवाद से निपटने में देशभर की पुलिस के लिए आदर्श बनेगा। उन्होंने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के पहले चरण का भी लोकार्पण किया। लगभग 857 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन और कंप्यूटर सेंटर (सी4आई) दिल्ली की जनता को समर्पित किया गया। इसके साथ 11 जिला स्तरीय सी3आई केंद्र और 75 थाना स्तरीय सी2आई इकाइयां भी जोड़ी गईं।

कक्षा 10 की पहली बोर्ड परीक्षा में शामिल होना सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य : सीबीएसई

नई दिल्ली, 16 फरवरी 2026। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने वर्ष 2026 से कक्षा 10 में लागू की जा रही दो बोर्ड परीक्षा प्रणाली के संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि पहली बोर्ड परीक्षा में शामिल होना सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होगा। इसे किसी भी स्थिति में छोड़ा नहीं जा सकता। बोर्ड ने 14 फरवरी को जारी अधिसूचना में कहा कि उसे कुछ अनुसूचित जाति प्रमुख धर, जिनमें यह मांग की गई थी कि यदि कोई छात्र किसी कारणवश पहली बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता है, तो उसे सीधे दूसरी बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। इस पर सीबीएसई ने अपनी नीति स्पष्ट करते हुए कहा कि दूसरी परीक्षा, पहली परीक्षा का विकल्प नहीं है, बल्कि यह प्रदर्शन सुधार और पात्र श्रेणियों के लिए अतिरिक्त अवसर है।



लैंड फॉर जॉन्स मामले में लालू परिवार पर आरोप तय कोर्ट ने कहा... निजी जागीर की तरह किया इस्तेमाल
नई दिल्ली, 16 फरवरी 2026। लैंड फॉर जॉन्स मामले में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की राजज जेपीपीटी कोर्ट ने सोमवार को इस बहुचर्चित मामले में लालू यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव समेत कुल 41 आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए। अदालत के इस फैसले के साथ ही अब मामले में नियमित ट्रायल का रास्ता साफ हो गया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी करते हुए इसे प्रथम दृष्टया संगठित साजिश करार दिया। अदालत ने कहा कि जांच में यह संकेत मिलता है कि रेल मंत्रालय को कथित तौर पर निजी जागीर की तरह इस्तेमाल किया गया और सरकारी नौकरियों को सौदेबाजी के माध्यम के रूप में उपयोग कर संपत्तियां अर्जित की गईं।

पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने लिया बड़ा एक्शन एसआईआर के काम में गड़बड़ी को लेकर 7 अधिकारी सस्पेंड

नई दिल्ली, 16 फरवरी 2026। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मामले में चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण के काम में गड़बड़ी को लेकर सात अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। चुनाव आयोग ने ये एक्शन इन अधिकारियों के खिलाफ गंभीर कदाचार, कर्तव्य की अवहेलना और एसआईआर शक्तियों के दुरुपयोग के पुख्ता सबूत मिलने के मामले में लिया है।

चुनाव आयोग ने सस्पेंड किए सात अधिकारी : चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 सीसी के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है और सभी सात अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश दिए हैं। चुनाव



आयोग ने सात अधिकारियों को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं, उन अधिकारियों में मुर्शिदाबाद के समसरेगंज से एईआरओ डॉ. सफ़ी उर्रहमान, फरका के एईआरओ नीतीश दास, मैनागुड़ी की डालिया रे चौधरी, सूती ब्लॉक के एसके मुर्शिद आलम, दक्षिण 24 परगना के कैमिंग पुरबो निर्वाचन क्षेत्र से एआरओ सत्यजीत दास, जायदीप कुंडू, डेबरा विधानसभा क्षेत्र से संयुक्त बीडीओ और एआरओ देवाशीष बिस्वास हैं। चुनाव आयोग से साफतौर पर कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

डीपफेक और गलत सूचनाएं समाज की नींव पर हमला, तकनीकी, कानूनी समाधान जरूरी : वैष्णव

नई दिल्ली, 16 फरवरी 2026। सूचना एवं प्रसारण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एआई इम्पैक्ट समिट से पहले डीपफेक, गलत एवं भ्रामक सूचनाओं के प्रसारण पर कहा कि यह प्रवृत्ति समाज की नींव पर हमला है। समाज की नींव संस्थाओं के बीच विश्वास है। परिवार, सामाजिक पहचान और शासन जैसी संस्थाएं सदियों से समाज को जोड़कर रखती हैं, लेकिन डीपफेक और भ्रामक सूचनाओं का तेजी से फैलना इन संस्थाओं के बीच विश्वास को कमजोर कर रहा है। वैष्णव ने यहां भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो के उद्घाटन से पहले एक सत्र में कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एआई मॉडल और उनके निर्माता सभी को जिम्मेदारी लेनी होगी कि नई तकनीक विश्वास को मजबूत करें, न कि उसे तोड़े। इसके लिए तकनीकी एवं कानूनी समाधान जरूरी हैं। अगर नई तकनीक संस्थाओं के बीच विश्वास को कमजोर करती है और विकल्प नहीं देती, तो यह समाज के लिए खतरनाक होगा। मंत्री वैष्णव ने कहा कि उन्होंने 20 से अधिक देशों के मंत्रियों से इस विषय पर बातचीत की है।

अमेरिका के साथ व्यापार समझौता देश के किसानों के लिए खतरा : कांग्रेस

नई दिल्ली, 16 फरवरी 2026। कांग्रेस ने भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते से देश के किसानों और जैविक विविधता पर सीधा खतरा बताया। पार्टी ने कहा कि खेती, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार की शर्तें, ये तीन सबसे अहम मुद्दे हैं, जिन पर सरकार ने देशहित को दांव पर लगा दिया है। कांग्रेस महासचिव एवं सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोमवार को यहां पार्टी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में कहा कि छह फरवरी को जारी हुई रूपरेखा अंतरिम समझौते के पहले ही बिंदु में यह तय किया गया है कि भारत अमेरिका से खाद्य और कृषि उत्पादों का आयात बिना किसी शुल्क के करेगा। यह भारतीय किसानों की आजीविका पर सीधा हमला है। अमेरिका से बिना आयात कर के मक्का, ज्वार और सोयाबीन ऑयल आयात होने पर भारत के किसानों को भारी नुकसान होगा।



अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश दिए हैं। चुनाव

महिलाओं के साथ धार्मिक और धार्मिक स्थलों पर हो रहे भेदभाव पर सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट की जांबो बैच

नई दिल्ली, 16 फरवरी 2026। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि 9 जनों की एक बैच महिलाओं के साथ धार्मिक और धार्मिक स्थलों पर होने वाले भेदभाव से जुड़े याचिकाओं पर सात अप्रैल से आखिरी सुनवाई शुरू करेगी। इसमें केरल के सबरीमाला मंदिर पर आए फैसले की समीक्षा का मामला शामिल है। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की एक



बैच ने कहा कि इस मामले में भारत के चीफ जस्टिस 9 सदस्यीय संवैधानिक बैच का गठन करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों से कहा है कि वे 14 मार्च या

इसके पहले अपनी लिखित दलीलें दायर करें। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र की ओर से कहा कि हमारी ओर से सबरीमाला फैसले की समीक्षा के लिए दायर याचिका का समर्थन किया है। सबरीमाला पर सुनाए गए फैसले में केरल में पहाड़ी पर स्थित पवित्र मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को घुसने की अनुमति दी गई है। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बैच ने सबरीमाला फैसले की समीक्षा का समर्थन करने वाले सभी पक्षों के लिए वकील कृष्ण कुमार सिंह को नोडल काउंसल बनाया है। वहीं इस फैसले की समीक्षा की मांग का विरोध करने वालों के लिए शारवती परी को नोडल काउंसल नियुक्त किया है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, हम यह भी उचित मानते हैं कि वरिष्ठ वकील के परमेश्वर के साथ शिवम सिंह को एमीकस नियुक्त किया जाए।

मैनपाट महोत्सव का भव्य समापन, सांसद श्री चिंतामणि महाराज रहे मुख्य अतिथि मैनपाट महोत्सव सरगुजा जिले की पहचान, आने वाले वर्षों में होगा और भव्य आयोजन : सांसद

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से गुलजार रही महोत्सव की शाम, कवि सम्मेलन ने बांधा समा



-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 16 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक वैभव के लिए प्रसिद्ध मैनपाट में आयोजित तीन दिवसीय मैनपाट महोत्सव 2026 का समापन समारोह उत्साह एवं गरिमामय वातावरण में सम्पन्न हुआ। समापन अवसर पर सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री चिंतामणि महाराज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

मुख्य अतिथि सांसद श्री चिंतामणि महाराज ने अपने संबोधन में महोत्सव के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों एवं समस्त क्षेत्रवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह महोत्सव केवल सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि सरगुजा की पहचान और गौरव का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा शुभारंभ अवसर पर जिले को विकास कार्यों की महत्वपूर्ण सौगात दी गई है, जिससे क्षेत्र में अधोसंरचना और पर्यटन को नई दिशा मिलेगी। सांसद ने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में मैनपाट निरंतर आगे बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में यह महोत्सव और अधिक भव्य एवं आकर्षक स्वरूप में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने उपस्थित जनसमुदाय को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि तीन दिवसीय आयोजन के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, लोककला, पारंपरिक व्यंजनों एवं मनोरंजन गतिविधियों ने पर्यटकों को आकर्षित किया है। समापन समारोह में सीतापुर विधायक श्री रामकुमार टोपो ने अपने संबोधन में कहा



कि मैनपाट महोत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि स्थानीय संस्कृति, परंपरा और प्रकृति से जुड़ाव का माध्यम है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा मैनपाट में पर्यटन विकास हेतु 1 करोड़ रुपये की राशि की घोषणा की गई है, जिससे क्षेत्र में पर्यटन अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी। उन्होंने आयोजन की सफलता के लिए सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने तीन दिवसीय महोत्सव के अंतर्गत आयोजित सांस्कृतिक संध्या, खेल प्रतियोगिताएं, स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी, पर्यटन गतिविधियां एवं अन्य आकर्षक कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, अमोलक सिंह (डिल्लो) सहित स्थानीय आयोजन से जुड़े सभी सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैनपाट

पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है और भविष्य में यह आयोजन और अधिक व्यापक स्वरूप में आयोजित किया जाएगा। समापन समारोह में जिला पंचायत सदस्य रतनी नाग, जनपद पंचायत मैनपाट अध्यक्ष संतोषी पैकारा, उपाध्यक्ष श्री अनिल सिंह, ग्राम पंचायत रोपाखार के सरपंच श्री सुखुराम, जनप्रतिनिधि श्री आलोक दुबे, श्री रजनीश पाण्डेय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश अग्रवाल, डीएफओ श्री अभिषेक जोगावत, जिला पंचायत सीईओ श्री विनय कुमार अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्री सुनील नायक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमोलक सिंह (डिल्लो) सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर की धमाकेदार प्रस्तुति के साथ मैनपाट महोत्सव 2026 का हुआ भव्य समापन

जिले में 13 से 15 फरवरी तक आयोजित तीन दिवसीय मैनपाट महोत्सव 2026 का भव्य समापन रविवार को उत्साह, उल्लास और सांस्कृतिक गरिमा के साथ सम्पन्न हुआ। अंतिम दिवस के मुख्य आकर्षण के रूप में बॉलीवुड की सुप्रसिद्ध गायिका कनिका कपूर की लाइव प्रस्तुति ने समापन समारोह को यादगार बना दिया। कनिका कपूर ने अपने लोकप्रिय गीत 'चिटियां कलाइयां', 'बेबी डॉल', 'यार ना मिले' सहित कई सुपरहिट बॉलीवुड गीतों की प्रस्तुति दी, जिस पर हजारों की संख्या में उपस्थित दर्शक झूम उठे। महोत्सव स्थल तालियों और उत्साह से गुंजाता रहा। कार्यक्रम में रायगढ़ के कलाकार राकेश शर्मा ने भक्ति, सूफी एवं लोकगीतों की प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से राजी रंगारज संख्या

महोत्सव की अंतिम शाम गीत-संगीत, नृत्य और नाट्य प्रस्तुतियों से सराबोर रही। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर प्रस्तुत शिव भजन एवं शिव ताण्डव नृत्य विशेष आकर्षण का केंद्र रहे, जिन्होंने आध्यात्मिक वातावरण का सृजन किया। स्थानीय कलाकारों में राहुल मण्डल, मानवी भगत, जय किशन विश्वास, शिवम सिन्हा सहित अन्य प्रतिभाओं ने अपनी सशक्त प्रस्तुतियों से दर्शकों की सराहना प्राप्त की। अन्य जिलों से आए कलाकारों में कोरिया जिले के सचिन्द्र कुमार एवं मनेन्द्रगढ़ की जसमीत कौर ने गीत-संगीत की मनमोहक प्रस्तुति दी। बिलासपुर की नृत्यांगना ज्योति श्री शिवम सिन्हा सहित अन्य प्रतिभाओं ने अपनी सशक्त प्रस्तुतियों से दर्शकों की सराहना प्राप्त की। अन्य जिलों से आए कलाकारों में कोरिया जिले के सचिन्द्र कुमार एवं मनेन्द्रगढ़ की जसमीत कौर ने गीत-संगीत की मनमोहक प्रस्तुति दी। बिलासपुर की नृत्यांगना ज्योति श्री शिवम सिन्हा सहित अन्य प्रतिभाओं ने अपनी सशक्त प्रस्तुतियों से दर्शकों की सराहना प्राप्त की।

सांसद श्री चिंतामणि महाराज ने किया विभागीय स्टॉलों का अवलोकन

मैनपाट महोत्सव के अवसर पर सांसद श्री चिंतामणि महाराज ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन कर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन और लाभार्थियों तक पहुंच के संबंध में चर्चा की तथा आमजन तक अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के स्टॉल में वीबी राम जी तथा अटल पंचायत डिजिटल केंद्र की जानकारी प्रदर्शित की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों का आकर्षक प्रदर्शन किया गया, जिसे सांसद ने सराहा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के स्टॉल में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना तथा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की जानकारी दी गई। समाज कल्याण विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं के साथ नशामुक्ति विषय पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। आदिवासी विकास विभाग ने पीएम जनमन योजना सहित जनजातीय संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए पारंपरिक आभूषण, जड़ी-बूटियां एवं उपयोगी सामग्री प्रदर्शित की। कृषि विभाग द्वारा दलहन आत्मनिर्भर मिशन (2025-31) पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। केंद्रीय जेल द्वारा बर्दियों के कोशल से निर्मित सामग्रियों का प्रदर्शन किया गया। रेशम विभाग ने रेशम की छती एवं प्रसंस्करण से संबंधित जानकारी के साथ निर्मित वस्तुओं का प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा हस्तशिल्प के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर आधारित प्रदर्शनी तथा वन विभाग द्वारा वन संपदा पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई।

साकार किया। आनंद कुमार गुप्ता मयारी आर्ट ग्रुप द्वारा प्रस्तुत भजन, संगीत एवं लोकनृत्य ने भी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। विविध सांस्कृतिक विधाओं का समावेश महोत्सव को बहुंगी और बहुआयामी स्वरूप प्रदान करता रहा।

बिलुप्त होती स्थानीय भाषा को लेकर आयोग के प्रांतीय अध्यक्ष ने साहित्यकारों से की चर्चा

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 16 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ राज भाषा आयोग के प्रांतीय अध्यक्ष डॉ. प्रभात मिश्रा 14 फरवरी को दो दिवसीय दौर पर अम्बिकापुर पहुंचे थे। उन्होंने सर्किट हाउस में जिले के साहित्यकारों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने स्थानीय बोली के प्रचार प्रसार को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की स्थानीय भाषा के उत्थान के लिए आयोग के माध्यम से किस प्रकार कार्य किया जा सकता है। आप सभी आलेख के माध्यम से अपने सुझाव आयोग को प्रेषित करें, जिससे हम उसके अनुरूप कुछ कार्य कर पाएं। साहित्यकारों से प्रभात मिश्रा ने कहा कि आप सभी उन बोलियों पर कार्य करें जो बिलुप्त होने के कगार पर हैं, हम उन्हें संरक्षित कैसे करें ये कार्य करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर आयोग के जिला समन्वयक राजेश तिवारी, डॉ. सुधीर पाठक, रंजीत सारथी, डॉ. अंचल सिन्हा और देवेन्द्र दुबे ने भी अपने-अपने विचार रखे। बैठक में साहित्यकार बीडी लाल, डॉ. दीपलता देशमुख, आशा पांडेय, अजय श्रीवास्तव, अनिल त्रिपाठी, मुकुंद लाल साहू, कृष्णा कान्त पाठक, राजेश पांडेय, संतोष दास, डॉ. उमेश पांडेय, माधुरी जायसवाल, राज लक्ष्मी पांडेय, निलिमा जायसवाल सहित अन्य शामिल रहे।

आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पद पर भर्ती हेतु 02 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 16 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

एकीकृत बाल विकास परियोजना अम्बिकापुर (शहरी) के परियोजना अधिकारी ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी सहायिका के 01 रिक्त पद हेतु खुली भर्ती से आवेदन 02 मार्च तक आमंत्रित किये गये हैं। आंगनबाड़ी सहायिका हेतु नेताजी सुभाषचंद्र बोस वाई क्र. 22 आंगनबाड़ी केंद्र तकिद्या रोड केदारपुर में भर्ती की जानी है। जिसकी सुवी एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं आयुक्त नगर पालिका निगम अम्बिकापुर के नोटिस बोर्ड में चर्चा कर दी गई है। इस हेतु केवल महिला ही आवेदन कर सकती हैं वे अपना आवेदन पत्र बाल विकास परियोजना अम्बिकापुर (शहरी) में कार्य दिवस पर कार्यालयीन समय पर जमा अथवा पंजीकृत डाक द्वारा निर्धारित अवधि तक भेज सकते हैं।

10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा : सरगुजा में 17,759 विद्यार्थी होंगे शामिल, बनाए गए 75 परीक्षा केंद्र

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 16 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल हयर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा वर्ष 2026 की शुरुआत 20 फरवरी से होने जा रही है। परीक्षा को लेकर जिले में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सोमवार को अम्बिकापुर स्थित मल्टीपरपज स्कूल से परीक्षा की गोपनीय सामग्री का वितरण सभी परीक्षा केंद्राध्यक्षों को किया गया। सामग्री वितरण के दौरान पूरे दिन गतिविधियां तेज रहीं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा संचालित हाईस्कूल एवं हयर सेकेंडरी परीक्षा वर्ष 2026 हयर सेकेंडरी 20 फरवरी से 18 मार्च तक तथा हाईस्कूल



परीक्षा 21 फरवरी से 12 मार्च तक आयोजित होगी। इस वर्ष जिले में हाई स्कूल एवं हयर सेकेंडरी परीक्षा के लिए 75 केन्द्र निर्धारित किए गए हैं। इसमें 17 हजार 759 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। सोमवार

को परीक्षा की गोपनीय सामग्री का वितरण अम्बिकापुर मल्टीपरपज स्कूल से किया गया। परीक्षा सामग्री लेने के बाद केंद्राध्यक्षों ने मिलान कर समन्वयक केन्द्र में ही पेटेटी में सील की। इसके

बाद निर्धारित रूट वाली टीम को एक साथ बस में बैठाकर पुलिस की सुरक्षा में रवाना किया गया। केंद्राध्यक्षों ने परीक्षा सामग्री अपने-अपने नजदीक के थाने पुलिस चौकी में लेकर जाकर पुलिस की मौजूदगी में थाने से गोपनीय सामग्री दी जाएगी। थानों में सुरक्षित रखी गई गोपनीय सामग्री : परीक्षा सामग्री लेने के बाद केंद्राध्यक्षों ने समन्वयक केंद्र में दस्तावेजों का मिलान कर पेटिटों को सील किया। इसके बाद निर्धारित रूट के अनुसार सभी टीमों को पुलिस सुरक्षा में बसों के माध्यम से रवाना किया गया। गोपनीय सामग्री जिले के 14 थाना एवं चौकियों में कड़ी सुरक्षा के बीच रखी गई है। परीक्षा के दिन पुलिस की मौजूदगी में सामग्री केंद्राध्यक्षों को सौंपी जाएगी।

ग्रामीणों ने रेंजर-गार्ड पर 20 एकड़ वन भूमि बेचने का लगाया आरोप

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 16 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा वन मंडल के अंतर्गत वन परिषद अम्बिकापुर के बीट खालिबा में वन भूमि को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामीणों ने रेंजर और फॉरेस्ट गार्ड पर मिलीभगत कर 20 एकड़ से अधिक वन भूमि को छोड़ने और अवैध तरीके से नई



नितार और आवागमन के रास्ते को भी बंद कर दिया गया, जिससे ग्रामीणों को

पेशानी हो रही है। ग्रामीणों द्वारा विरोध करने पर रेंजर एवं वन कर्मियों द्वारा सुनवाई नहीं की गई, बल्कि उन्हें धमकाने की बात भी सामने आई है। जंगल और वन भूमि की सुरक्षा को लेकर गांव की महिलाएं भी बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल हुईं। ग्रामीणों का कहना है कि वन क्षेत्र में अवैध कब्जा और भूमि के दुरुपयोग को किसी भी हालत में स्वीकार

नहीं किया जाएगा। शिकायत मिलने के बाद मुख्य वन संरक्षक सरगुजा दिलराज प्रभाकर ने वनमंडलाधिकारी सरगुजा को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा ऐसे मामलों में सहयोग करने वाले विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

घोटाला करो, सस्पेंड हो... फिर बहाल होकर वापस आओ! भैयाथान सहकारी बैंक बना 'री-एंट्री सेंटर'?

घोटाला करो...सस्पेंड हो...फिर बहाल होकर लौट आओ! सहकारिता विभाग का नया फॉर्मूला?

- 2.25 करोड़ पशुपालन से 35 लाख बीमा तक-भैयाथान शाखा में आरोपित अफसरों की वापसी पर बवाल
- बैंक या 'री-एंट्री क्लब'? कार्रवाई झेल चुके मैनेजर्स की बहाली पर उठे सवाल
- सूटकेस की ताकत या राजनीतिक एप्रोच? भैयाथान बैंक में अंदरखाने खेल की चर्चा
- जांच रिपोर्ट फाइलों में...बहाली की तैयारी मैदान में... सहकारिता विभाग की चुप्पी क्यों?
- अजीत सिंह की वापसी के बाद जगदीश कुशवाहा की बहाली की चर्चाएं तेज, बैंक बोर्ड की भूमिका पर भी निगाहें

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर, 16 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

सहकारिता विभाग में नियम-कायदे किताबों तक सीमित है या जमीन पर भी लागू होते हैं - यह सवाल इन दिनों जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर की भैयाथान शाखा को लेकर जोर पकड़ रहा है, वजह है दो नाम, दो बड़े घोटाले और अब बहाली की चर्चाओं का नया अध्याय, आरोप है कि जिन अधिकारियों पर करोड़ों की अनियमितताओं के साए रहे, वही अब फिर से सिस्टम में लौटने की तैयारी में हैं।

पहला अध्याय: अजीत सिंह और 2.25 करोड़ का पशुपालन ऋण प्रकरण

भैयाथान शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक अजीत सिंह का नाम उस समय सुर्खियों में आया था, जब पशुपालन ऋण वितरण में करीब 2 करोड़ 25 लाख रुपये की गड़बड़ी के आरोप लगे, कलेक्टर कार्यालय के आदेश पर गठित जांच टीम की रिपोर्ट में कई हितग्राहियों के नाम पर फर्जी या संदिग्ध ऋण वितरण, दरतावेजों की कमी और निरामों की अनदेखी जैसे बिंदु सामने आए थे, जांच में यह भी सामने आया कि कई मामलों में पशु मौजूद ही नहीं थे, लेकिन कागजों में ऋण पास हो गया, सवाल यह उठा कि क्या बैंक की आंखें बंद थीं या किसी ने जानबूझकर परदे गिरा दिए थे?

दूसरा अध्याय: जगदीश कुशवाहा और 35.38 लाख का फसल बीमा विवाद

इसके बाद चर्चा में आया दूसरा नाम-जगदीश कुशवाहा, जो तत्कालीन शाखा प्रबंधक रहे। आरोप है कि उनके कार्यकाल में करीब 35 लाख 38 हजार रुपये के फसल बीमा प्रकरण में अनियमितताएं सामने आईं, स्थानीय स्तर पर यह मामला लंबे समय तक चर्चाओं में रहा, लेकिन अंतिम कार्रवाई और जवाबदेही को लेकर आज भी कई सवाल हवा में तैर रहे हैं।

बहाली की 'इनसाइड स्टोरी' सिस्टम मजबूत या मेहरबानी?

सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि पहले कार्रवाई झेल चुके अजीत सिंह की बहाली हो चुकी है और अब उन्हें के जिए जगदीश कुशवाहा की वापसी का रास्ता तैयार होने की बात कही जा रही है, सूत्रों का दावा है कि अंबिकापुर में बैठकों और संपर्कों का दौर जारी है। हालांकि बैंक या सहकारिता विभाग की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन अंदरखाने चल रही हलचल ने कर्मचारियों और आम लोगों के बीच सवालों का तूफान खड़ा कर दिया है।

भैयाथान सहकारी बैंक

घोटाला करो... सस्पेंड हो...

फिर बहाल होकर लौट आओ!

सहकारिता विभाग का नया फॉर्मूला?



जगदीश, अजीत

- अजीत सिंह से जगदीश कुशवाहा तक सिस्टम पर सवाल
- 2.25 करोड़ पशुपालन से 35 लाख बीमा तक — भैयाथान शाखा में...

'मेहरबानी' किसकी-बोर्ड की, बैंक की या राजनीति की?

बैंक गलियों में चर्चा है कि घोटाले के आरोप झेल चुके अधिकारियों पर अचानक इतनी नरमी क्यों दिखाई जा रही है, कुछ लोग इसे राजनीतिक एप्रोच का असर बता रहे हैं, तो कुछ इसे 'सूटकेस वाली संस्कृति' की उपज कहकर तंज कस रहे हैं, सवाल यह भी है कि अगर आरोप गंभीर थे, तो बहाली इतनी आसान कैसे हो गई? और अगर आरोप गलत थे, तो फिर कार्रवाई क्यों हुई?

सहकारिता विभाग की साख पर बड़ा प्रश्नचिह्न

भैयाथान शाखा में बार-बार सामने आ रहे विवादों ने सहकारिता विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, कर्मचारियों का कहना है कि अगर आरोपित अधिकारियों की वापसी बिना स्पष्ट जवाबदेही के होती है, तो इससे यह संदेश जाएगा कि 'पहले घोटाला करो, फिर सिस्टम में रास्ता निकाल लो'।

जनता पूछ रही है... जवाब कौन देगा?

- क्या जांच रिपोर्ट सिर्फ फाइलों में बंद रखने के लिए बनती है?
- क्या सहकारिता बैंक में नियमों से ज्यादा 'सिफारिश' चलती है?
- और क्या भैयाथान शाखा सच में 'घोटाला करो और बहाल हो जाओ' मॉडल पर चल रही है?
- इन सवालों के बीच बैंक प्रबंधन और सहकारिता विभाग की चुप्पी ही सबसे ज्यादा चर्चा में है।

अंबिकापुर में संभाग स्तरीय रोजगार मेला शुरू...2000 युवाओं का पंजीयन 4544 पदों पर रोजगार का अवसर



-संवाददाता-

अम्बिकापुर, 16 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा जिले के शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, अंबिकापुर में दो दिवसीय संभाग स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन सरगुजा संसद श्री चिंतामणि महाराज के मुख्य आतिथ्य एवं जिला पंचायत सरगुजा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनय कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में किया गया। संभाग स्तरीय रोजगार मेले में संभाग के सभी 6 जिलों से लगभग 2000 बेरोजगार नवयुवक एवं नवयुवतियों ने ऑनलाइन पंजीयन कराया। संभाग मुख्यालय में आयोजित रोजगार मेले में लगभग 29 नियोजकों ने भाग लेकर युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए। संभागीय उप संचालक रोजगार श्री एस.पी. त्रिपाठी ने बताया कि रोजगार मेला 16 एवं 17 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 4544 पदों पर ऑनलाइन आवेदन एवं साक्षात्कार के आधार पर युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। मुख्य अतिथि संसद श्री चिंतामणि महाराज ने उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए सकारात्मक सोच के साथ अपने कैरियर को नई ऊंचाई देने का संदेश दिया। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा श्री विनय अग्रवाल तथा पॉलीटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य श्री आर.जे. पाण्डेय ने भी युवाओं को प्रेरित किया। स्वागत प्रतिवेदन जिला रोजगार अधिकारी श्री ललित पटेल ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन श्री रवि पाण्डेय एवं आभार प्रदर्शन लाइवलीहूड कॉलेज के प्राचार्य श्री गिरिश गुप्ता ने किया। रोजगार मेले में जिला रोजगार अधिकारी सूरजपुर सुश्री चारु चित्रा, श्री संजीव सिंह, श्री दिव्यांशु, श्री प्रीतम, सुश्री माधुरी, श्रीमती पुष्पा पुरेना, श्रीमती पुष्पा सिदार, श्री नीरज सिंह, श्री छोटू रविदास, श्री उदय शंकर मिरे, श्री रामेश्वर सिंह तथा जिला रोजगार कार्यालय के समस्त स्टाफ, श्री अकरम खान, श्री अरशद, श्री राहुल, श्री बालेश्वर सहित अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों का सक्रिय सहयोग रहा।

महाशिवरात्रि पर महाकाल मोक्षधाम में शमशान घाट पर विशेष शिव पूजन



-संवाददाता-

अम्बिकापुर, 16 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

महाशिवरात्रि के अवसर पर महाकाल मोक्षधाम शंकर घाट स्थित महाकाल बाबा मंदिर परिसर में विशेष शिव पूजन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर को पत्थरी झड़ों से आकर्षक रूप से सजाया गया। गुरुजी बालमनाथ अचारी एवं अशोक शर्मा द्वारा अचोर शास्त्रोक्त विधि से महाकाल बाबा की पूजा-अर्चना की गई। पूजन के दौरान महाकाल बाबा शिव से प्रार्थना की गई कि देश में अमन-चैन बना रहे और सभी नागरिक आपसी भाईचारे के साथ रहें। बालमनाथ अचारी उज्जैन के चक्रतीर्थ शमशान के योगी बाबा बमबम नाथ एवं अचल नाथ महाराज के शिष्य बताए गए हैं।

अवैध बॉक्सऑट खनन कार्रवाई में ग्रामीण की मौत, एसडीएम समेत 4 पर हत्या का केस चारों आरोपी गिरफ्तार, कुसमी में तनाव, आदिवासी समाज का प्रदर्शन



-संवाददाता-

अम्बिकापुर, 16 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

क्षेत्र में अवैध बॉक्सऑट खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान हुई मारपीट में एक ग्रामीण की मौत का मामला गंभीर हो गया है। पुलिस ने मर्ग जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर एसडीएम समेत चार लोगों के खिलाफ हत्या सहित गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना के बाद नगर में भारी पुलिस बल तैनात है और देर शाम तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही।

जानकारी के अनुसार कुसमी थाना क्षेत्र के ग्राम हंसपुर से लगे झारखंड के लुचुतपाट इलाके में अवैध बॉक्सऑट खनन की सूचना पर प्रशासनिक टीम पहुंची थी। आरोप है कि घुंसा पाट रोड स्थित महादेव डूबा नाला के पास रात करीब 8-9 बजे एसडीएम सहित साथ मौजूद लोगों ने तीन ग्रामीणों के साथ डंडे, रॉड व हथ-लात से मारपीट की। घटना में 62 वर्षीय राम उर्फ रामनेश की गंभीर चोटों से मौत हो गई, जबकि अजीत राम (60) और आकाश अग्रिया (20) घायल हो गए। दोनों का उपचार जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मारपीट के बाद टीम हंसपुर की महिला उपसरपंच गीता देवी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना के घटने पर पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया।

तैज रफ्तार और वाहन पर नियंत्रण खोना दुर्घटना का मुख्य कारण : हदसे में चालक सोनू अग्रिया



पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हत्या का अपराध दर्ज

पुलिस ने चरमदीय गवाहों के बयान, घटनास्थल निरीक्षण और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पाया कि 15 फरवरी 2026 की रात आरोपियों द्वारा मारपीट की गई थी। प्रथम दृष्टया अपराध सिद्ध पाए जाने पर एसडीएम करुण कुमार डहरिया, अजय प्रताप सिंह उर्फ विक्रमी सिंह, मजीत कुमार यादव और सुदीप यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 115(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया।

इलाज के दौरान मौत, मर्ग से शुरू हुई जांच

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार घायल रामनेश को बेहोशी की हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुसमी लाया गया था। प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रेफर किया गया, लेकिन आगे नहीं ले जाया जा सका। 16 फरवरी की रात 12.14 बजे उनकी मृत्यु हो गई। चिकित्सक की सूचना पर मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई थी।

आदिवासी समाज में आक्रोश, शव का अंतिम संस्कार रोका

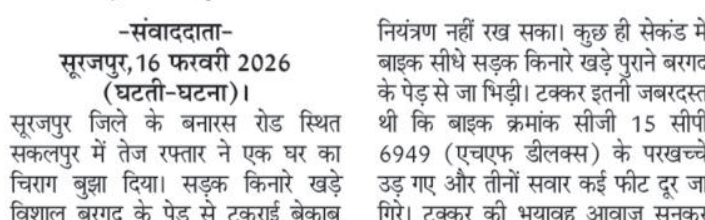
घटना के बाद सर्व आदिवासी समाज में भारी आक्रोश है। समाज के लोगों ने मोटरसाइकिल रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। बेलगंगा नदी पुलिस के पास देर शाम तक गहमा-गहमी की स्थिति बनी रही। प्रशासन ने मृतक के परिजनों को तात्कालिक सहायता के रूप में एक लाख रुपए तथा मृतक के तीन बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने का आश्वासन दिया है। वहीं समाज के लोग पांच करोड़ रुपए मुआवजा सहित अन्य मांगों पर अड़े हैं और शव का अंतिम संस्कार नहीं करने दे रहे हैं।



स्थिति पर नजर विवेचना जारी

नगर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अपर कलेक्टर सहित कई थाना-चौकियों का बल तैनात किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तृत विवेचना जारी है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। इधर, क्षेत्र के कई लोगों ने एसडीएम की कार्यप्रणाली को लेकर पहले ही नाराजगी की बात कही है। प्रशासन ने मामला सामान्य करने के प्रयास में जुटा है।

बनारस रोड पर मौत की दस्तक! बरगद से टकराई बेकाबू बाइक, 17 वर्षीय चालक की दर्दनाक मौत, दो नाबालिग घायल



-संवाददाता-

सूरजपुर, 16 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

सूरजपुर जिले के बनारस रोड स्थित सकलपुर में तेज रफ्तार ने एक घर का चिराग बुझा दिया। सड़क किनारे खड़े विशाल बरगद के पेड़ से टकराई बेकाबू बाइक ने ऐसा मंजर खड़ा किया कि पूरे इलाके में मातम पसर गया। हदसे में 17 वर्षीय किशोर की मौत हो गई, जबकि उसके साथ सवार दो अन्य नाबालिग घायल हो गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तीनों किशोर एक ही बाइक पर सवार होकर तेज गति से रफ्तार इतनी अधिक थी कि अचानक संतुलन बिगड़ते ही चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। कुछ ही सेकंड में बाइक सीधे सड़क किनारे खड़े पुराने बरगद के पेड़ से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक क्रशमैक सीजी 15 सीपी 6949 (एचएफ डीलक्स) के परखच्चे उड़ गए और तीनों सवार कई फीट दूर जा गिरे। टक्कर की भयावह आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंचे। सड़क पर खून से लथपथ पड़े किशोरों को देखकर हर कोई सन्न रह गया। तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया।



तैज रफ्तार और वाहन पर नियंत्रण खोना दुर्घटना का मुख्य कारण : हदसे में चालक सोनू अग्रिया

पिता मनोज उर्फ गेंठी, घायल हैं। दोनों का इलाज जारी है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त बाइक को सड़क से हटकर यातायात सुचारू कराया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और वाहन पर नियंत्रण खोना दुर्घटना का मुख्य कारण माना जा रहा है। यह हादसा एक बार फिर कम उम्र में वाहन चलाने की गंभीर समस्या को उजागर करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना कानूनन अपराध है और यह स्वयं तथा दूसरों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हेलमेट और अन्य सुरक्षा उपायों की अनदेखी भी हादसे

की भयावहता बढ़ा देती है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बनारस रोड पर अक्सर वाहन तेज गति से दौड़ते हैं। सड़क के किनारे बड़े पेड़ और कुछ स्थानों पर संकरी पट्टी होने के कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मार्ग पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं, चेतावनी संकेतक लगाए जाएं और नियमित पुलिस गश्त बढ़ाई जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। हादसे के बाद मृतक सोनू के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। दो अन्य परिवार अपने घायल बच्चों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। सकलपुर और आसपास के गांवों में शोक और चिंता का माहौल है।

विष्णुदेव साय के कोरिया प्रवास में गूंजा सवाल मुख्यमंत्री जी... हम बहुत तकलीफ में हैं, हमारा मानदेय तो दिलवा दीजिए...

-संवाददाता-
कोरिया, 16 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।
प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कोरिया जिला प्रवास के बीच एक ऐसा मुद्दा उभरकर सामने आया है, जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था की जमीनी हकीकत को उजागर कर दिया है, जिले की मितानिनें, ब्लॉक समन्वयक, स्वास्थ्य पंचायत समन्वयक और हेल्प डेस्क से जुड़ी कार्यकर्ता पिछले पाँच महीनों से लिखित मानदेय के भुगतान की मांग को लेकर आंदोलन की स्थिति में हैं, जिन महिलाओं को शासन स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ कहता है, वे आज खुद आर्थिक संकट के

आईसीयू में भर्ती हैं। कोरिया जिले में मितानिनें की यह पुकार केवल स्थानीय मुद्दा नहीं, बल्कि प्रदेशव्यापी व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न है, अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री के फेसले पर टिकी हैं, अगर शीघ्र समाधान निकलता है तो यह संदेश जाएगा कि सरकार जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है, अन्यथा, दिया तले अंधेरा वाली कहवात फिर सच साबित होगी। (यह समाचार संगठन प्रतिनिधियों, ज्ञापनों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर तैयार किया गया है, प्रशासन का आधिकारिक पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।)



आर्थिक संकट: परिवारों पर सीधा असर

1. **कर्ज का बोझ**
मानदेय न मिलने के कारण कई समन्वयकों ने निजी उधार लिया है। ब्याज दरें 2ब से 5 प्रतिशत मासिक तक बताई जा रही हैं, पाँच महीने की देरी ने कर्ज को दोगुना कर दिया।

2. **बच्चों की पढ़ाई प्रभावित**
स्कूल फीस जमा न होने से नोटिस मिल रहे हैं, कुछ परिवारों ने बच्चों को निजी स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में भेजने का निर्णय लिया।

3. **बुजुर्गों का इलाज अधूरा**
स्वास्थ्य कार्यकर्ता होने के बावजूद अपने घर के बुजुर्गों का इलाज कराने में असमर्थता विडंबना बन गई है, एक ब्लॉक समन्वयक ने नाम न छपाने की शर्त पर कहा-हम दूसरों के घर प्रसव के लिए रात में भी जाते हैं, लेकिन हमारे घर में राशन की चिंता बनी रहती है।

प्रशासनिक चुप्पी या तंत्र की जटिलता ?
स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों का तर्क है कि बजट आबंटन और तकनीकी स्वीकृति में विलंब के कारण भुगतान अटका है। परंतु सवाल यह है कि, जब योजनाओं की मॉनिटरिंग समय पर हो सकती है, तो भुगतान प्रक्रिया क्यों नहीं? विशेषज्ञों का मानना है कि मितानिनें प्रणाली सामुदायिक स्वास्थ्य मॉडल का अहम हिस्सा है। यदि इनके मनोबल में गिरावट आती है तो ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचा सीधे प्रभावित होगा।

मुख्यमंत्री प्रवास उम्मीद या औपचारिकता ?
मुख्यमंत्री के प्रवास को लेकर जिले में प्रशासनिक हलचल तेज है, कार्यक्रमों और घोषणाओं की तैयारी चल रही है, मितानिनें की अपेक्षा है कि मुख्यमंत्री उनके प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर स्पष्ट निर्देश देंगे। उनका कहना है- हमें भाषण नहीं, भुगतान चाहिए।

सेवा निरंतर, भुगतान बंद
मितानिनें गांव-गांव जाकर टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की निगरानी, कुपोषण सर्वे, मलेरिया-जांच, आयुष्मान पंजीयन और विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का क्रियान्वयन करती हैं। कोविड काल में भी इन्होंने घर-घर सर्वे कर जोखिम उठाया, लेकिन अबकूर माह से मानदेय अटका हुआ है, सूत्रों के अनुसार-प्रोत्साहन राशि आंशिक रूप से जारी हुई, भुगतान का स्पष्ट ब्योरा (राज्यांश-केंद्रांश) उपलब्ध नहीं, दावा पत्रक के मुकाबले राशि कम मिली, नियमित बजट प्रवाह बाधित बताया जा रहा है, मैदानी स्तर पर असंतोष गहरा है, परंतु जिम्मेदार विभागों की ओर से स्पष्ट जवाब अब तक सामने नहीं आया।

ज्ञापन से जनप्रतिनिधि तक: पर समाधान दूर
मितानिनें संगठन ने सीएमएचओ कार्यालय, जिला प्रशासन और राज्य स्तर तक ज्ञापन सौंपे हैं।
पुणेन्द्र राजवाड़े, अध्यक्ष कोरिया जन सहयोग समिति, ने कहा... मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। सरकार को शीघ्र लिखित भुगतान करना चाहिए ताकि इन महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरे। वहीं, **सरोज सिंह सेंगर**, प्रदेश अध्यक्ष, स्वास्थ्य मितानिनें संघ छत्तीसगढ़, का कहना है-ब्लॉक से राज्य स्तर तक गृहण लगा चुके हैं। अबकूर से फरवरी तक का मानदेय तुरंत जारी हो। परिवार चलाना मुश्किल हो गया है।

सामाजिक और राजनीतिक संदेश
यह मुद्दा केवल वेतन का नहीं, बल्कि व्यवस्था की संवेदनशीलता का भी है। यदि जमीनी स्तर की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता आर्थिक असुरक्षा में रहेंगी, तो योजनाओं की सफलता प्रभावित होगी, मुख्यमंत्री का यह दौरा प्रशासन के लिए एक परीक्षा भी है, क्या सरकार अपने स्वास्थ्य तंत्र की 'रीढ़' को मजबूती देगी, या फिर आश्वासन की परंपरा जारी रहेगी?



मुख्य मांगें...

अबकूर से लिखित 5 माह का पूरा मानदेय तत्काल जारी किया जाए।
प्रोत्साहन राशि में पारदर्शिता हो, राज्यांश और केंद्रांश का स्पष्ट उल्लेख मिले।
भविष्य में नियमित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए स्थायी बजट व्यवस्था बने।
हेल्प डेस्क व समन्वयकों की भूमिका को औपचारिक मान्यता मिले।

चिरमिरी में विकास की रफ्तार तेज: मुख्यमंत्री साय का दौरा



जनभागीदारी और राजनीतिक संदेश
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने कलश धारण कर स्वागत किया, अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधियों को गजमाला पहनाकर सन्मानित किया गया, यह दौरा केवल विकास कार्यों की घोषणा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक रूप से भी एक स्पष्ट संदेश देता दिखाई दिया-कि राज्य सरकार और क्षेत्रीय नेतृत्व के बीच समन्वय मजबूत है, किसी क्षेत्र में मुख्यमंत्री का बार-बार आगमन यह संकेत देता है कि वह क्षेत्र शासन की प्राथमिकता सूची में ऊपर है।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिलहरी जायसवाल की सक्रिय भूमिका से एमसीबी को मिली नई सौगात
चिरमिरी में विकास की बड़ी सौगात: 59 का शिलान्यास, 82 कार्यों का लोकार्पण
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दौरा, करोड़ों की योजनाओं से एमसीबी को नई रफ्तार
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिलहरी जायसवाल की पहल पर मुख्यमंत्री का आगमन
नवगठित एमसीबी जिले में अधोसंरचना को मिली मजबूती
करीब 127 करोड़ रुपये के विकास कार्यों से क्षेत्र में नई उम्मीद
मुख्यमंत्री का बार-बार चिरमिरी आगमन: क्या एमसीबी बना सरकार की प्राथमिकता जिला ?



-संवाददाता-
एमसीबी, चिरमिरी, 16 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।
नवगठित मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले की धरती पर एक बार फिर विकास की बड़ी सौगातें उतरें, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चिरमिरी पहुंचे, उनके साथ प्रभारी मंत्रोरामविचार नेताम भी मौजूद रहे, राजनीतिक हलकों में यह चर्चा रही कि यह दौरा स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिलहरी जायसवाल के विशेष आग्रह और आमंत्रण पर तय हुआ, बीते दो वर्षों में मंत्री जायसवाल द्वारा मुख्यमंत्री को अपने क्षेत्र में कई बार आमंत्रित किए जाने की चर्चा

है, जिसके चलते एमसीबी जिले में विकास कार्यों की गति लगातार तेज होती दिखाई दे रही है।
चिरमिरी दौरा एमसीबी जिले के लिए विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ, 59 कार्यों का शिलान्यास, 82 कार्यों का लोकार्पण, करोड़ों रुपये की योजनाओं का शुरुआत, इन सबके

हेलीपैड से मंगल भवन तक

मुख्यमंत्री सूरजपुर से चौपर द्वारा उड़ान भरकर पोड़ी गाँव स्थित हेलीपैड पहुंचे, यहां स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिलहरी जायसवाल, बैकुण्ठपुर विधायक भईया लाल राजवाड़े, कलेक्टर डी. राहुल वैकट एवं पुलिस अधीक्षक श्रीमती रतना सिंह ने आत्मीय स्वागत किया, हेलीपैड से मुख्यमंत्री का काफिला मालवीय नगर, पोड़ी स्थित मंगल भवन पहुंचा, जहां जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों से संवाद का कार्यक्रम आयोजित था। पारंपरिक रीति से चंदन टीका और कलश स्वागत के बाद टीका प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, राष्ट्रगान के सामूहिक गान के साथ वातावरण गरिमान्वय हो उठा।

8,824.78 लाख के 59 कार्यों का शिलान्यास

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 8,824.78 लाख रुपये (लगभग 88.24 करोड़ रुपये) की लागत से प्रस्तावित 59 विकास कार्यों का शिलान्यास किया, इनमें अधोसंरचना, सड़क, मग्न एवं अन्य जनहित परियोजनाएं शामिल हैं, यह कार्य नवगठित जिले के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और नागरिक सुविधाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

3,879.85 लाख के 82 कार्यों का लोकार्पण-

इसके साथ ही 3,879.85 लाख रुपये (लगभग 38.79 करोड़ रुपये) की लागत से पूर्ण 82 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया, इन कार्यों के पूर्ण होने से चिरमिरी क्षेत्र में सड़क, मग्न, पेयजल एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ता मिली है, मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार गांव से शहर तक विकास की धारा बहाने के लिए प्रतिबद्ध है और एमसीबी जैसे नवगठित जिलों को प्राथमिकता दी जा रही है।

'वंदे भारत' जैसी विकास गति

स्थानीय लोग व्यंग्य में कहते हैं कि जिला नया जल्द है, लेकिन विकास की रफ्तार वंदे भारत ट्रेन जैसी दिख रही है, लगातार शिलान्यास और लोकार्पण से यह संदेश गया है कि एमसीबी जिला सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासनिक सुविधाओं के विस्तार को लेकर योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है।

गोवर्धन पर्वत दियागढ़ धाम में महाशिवरात्रि पर भव्य भजन मेला व विशाल भंडारा संपन्न

विधायक भूलन सिंह मरावी रहे उपस्थिति

-संवाददाता-
सूरजपुर, 16 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।
महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर गोवर्धन पर्वत दियागढ़ धाम में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ भव्य भजन मेला एवं विशाल भंडारे का आयोजन संपन्न हुआ। ग्राम पंचायत गोकुलपुर, पम्पानगर एवं द्वारिकापुर के मध्य स्थित इस प्रमुख धार्मिक स्थल पर शिव मंदिर समिति द्वारा व्यापक तैयारियां की गई थीं, जिसके चलते कार्यक्रम सुव्यवस्थित एवं भव्य रूप में आयोजित हुआ। दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित भक्ति संगीत कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायक एम.डी. महंत ने शिव भजनों की मनमोहक प्रस्तुति दी, उनके भजनों पर श्रद्धालु भाव-विभोर हो उठे और 'हर-हर महादेव' के जयकारों से पूरा परिसर शिवमय हो गया, भजन संस्था के साथ-साथ विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक भूलन सिंह मरावी शामिल हुए, अपने संबोधन में उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन



समाज में एकता, सद्भाव और सांस्कृतिक चेतना को सुदृढ़ करते हैं, उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों का संरक्षण और विकास सामाजिक समरसता को मजबूत करता है, विधायक ने क्षेत्र के विकास एवं धार्मिक स्थलों के संवर्धन के लिए निरंतर प्रयास करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। कार्यक्रम की अध्यक्षता मेला समिति के अध्यक्ष परमेश्वर यादव ने की। इस आयोजन को सफल बनाने में मेला समिति के पदाधिकारियों, क्षेत्रीय सरपंचों, जनप्रतिनिधियों एवं समस्त ग्रामवासियों की सक्रिय भूमिका रही।

मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री की भूमिका
राजनीतिक विरोधों का मानना है कि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिलहरी जायसवाल केवल विभागीय जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे मुख्यमंत्री और क्षेत्रीय जनता के बीच एक तंतु की भूमिका निभा रहे हैं, प्रदेश की सियासत में यह चर्चा भी आम है कि यदि किसी कारणवश मुख्यमंत्री स्वयं उपस्थित नहीं हो पाते, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में जायसवाल ही कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और सरकार का संदेश जनता तक पहुंचाते हैं, उनकी सक्रियता के चलते क्षेत्र में जनसंवाद कार्यक्रम, विकास योजनाओं की समीक्षा और त्वरित निर्णय की छवि उभरकर सामने आई है।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (र.) अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0)

ईशतहार
रा.प्र.क्र./अ-2/2025-26

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुचित तिकी पिता रामलाल तिकी जाति उगंव निवासी बटवाही तहसील लुण्डा जिला सरगुजा (छ0ग0) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि स्थित ग्राम नवागढ़ तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0) खसरा नंबर 175/2 रकबा 0.024 हे० भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यवहृत करने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, नक्शा, भूमि उपयोगिता प्रमाण पत्र, सेटलमेंट, रजिस्ट्री की प्रति, आदि सहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है।
अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 24/2/2026 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निष्पत्ति समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
आज दिनांक 05/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।
(सील) अनुविभागीय अधिकारी (र.) अम्बिकापुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0)

ईशतहार
रा0प्र0क्र0-/-/अ-121/2025-26

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक विकी आर०स्व० कार्तिक निवासी मंडलपारा सुभाषनगर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0) के द्वारा ग्राम सुभाषनगर स्थित खसरा नंबर 149/3 रकबा 0.700 हे० में से रकबा 0.052 हे० भूमि को अनावेदक नीलम मिंज पति विनित कुमार मिंज निवासी बिचपारा रातासीली कुसमी जिला बलरामपुर (छ0ग0) के पास अंकन राशि रुपये 13,00,000/- में विक्री करने का सोदा तय कर विक्री अनुमति हेतु आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय सरगुजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो जांच एवं प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 11.03.2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
आज दिनांक 05/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।
(सील) तहसीलदार अम्बिकापुर, सरगुजा

सम्मान की सवारी या सादगी की राह ? अमृतधारा महोत्सव में प्रोटोकॉल बनाम प्रतिष्ठा की कहानी



**VIP बोर्ड लगी गाड़ी को
मुख्य पार्किंग में रोका गया**

VIP बनाम जनता

गाड़ी रोकी तो गुस्सा फूटा



**जब नेता जी गाड़ी रूकी,
तो गरिमा भी अटक गई?**

राजनीतिक प्रभाव से ऐसे घटनाक्रम के तीन संभावित प्रभाव होते हैं...

सार्वजनिक छवि पर असर-सादगी की जगह अहंकार की छवि बनती है। पार्टी की असहजता-उच्च नेतृत्व तक संदेश जाता है। प्रशासनिक तनाव-भविष्य में आयोजनों में और कड़ाई आती है, यह घटना केवल व्यक्तिगत नहीं रहती, बल्कि संस्थागत संदेश बन जाती है।

जनभावना बनाम राजनीतिक जिद

नेम प्लेट फेंकना और बहिष्कार करना क्षणिक प्रतिक्रिया हो सकती है, पर सार्वजनिक जीवन में हर प्रतिक्रिया सार्वजनिक संदेश होती है, यदि नियमों को मानते हुए मंच तक पैदल पहुंचा जाता, तो यह लोकतांत्रिक परिपक्वता का उदाहरण बन सकता था।

**मंच से पहले पार्किंग की लड़ाई: एमसीबी महोत्सव की अंदरूनी कहानी
अमृतधारा में अहंकार की आहट : प्रोटोकॉल, प्रतिष्ठा और लोकतंत्र की परीक्षा**

**अमृतधारा में अहंकार की धार : प्रोटोकॉल पर प्रतिष्ठा की राजनीति
सम्मान की भूख या प्रोटोकॉल की गलतफहमी ? एमसीबी महोत्सव का सच**

**नेम प्लेट बनाम नियम : अमृतधारा में सियासी तकरार
पैदल चलना अपमान ? अमृतधारा महोत्सव में उठे लोकतंत्र के सवाल**

प्रोटोकॉल का वैधानिक पक्ष

मंत्री का दर्जा- कैबिनेट मंत्री को राज्य सरकार के 'Order of Precedence' में उच्च स्थान प्राप्त होता है, उनके लिए निर्धारित सुरक्षा घेरा, विशेष पार्किंग, काफिला प्रवेश, मंच पर प्राथमिक आसन नियमित रूप से लागू होते हैं।

विधायक प्रतिनिधि- विधायक प्रतिनिधि कोई संवैधानिक पद नहीं होता, यह एक राजनीतिक नियुक्ति है, प्रशासनिक दर्जा नहीं, उन्हें मंत्री स्तर का प्रोटोकॉल स्वतः प्राप्त नहीं होता।

नगर पालिका अध्यक्ष- नगर पालिका अध्यक्ष स्थानीय निकाय का प्रमुख पद है, उन्हें मंचोपस्थान मिलना चाहिए- और मिला भी, परंतु मंत्री स्तर की पार्किंग और सुरक्षा का अधिकार स्वतः लागू नहीं होता, स्पष्ट शब्दों में-विधायक स्वयं उपस्थित हों तो उनके प्रतिनिधि के लिए अलग VIP प्रोटोकॉल का कोई कानूनी आधार नहीं बनता।

प्रशासनिक दृष्टिकोण- प्रशासन का तर्क सरल था सुरक्षा और प्रमुख पद है, उन्हें मंचोपस्थान मिलना चाहिए- और मिला भी, परंतु मंत्री स्तर की पार्किंग और सुरक्षा का अधिकार स्वतः लागू नहीं होता, स्पष्ट शब्दों में-विधायक स्वयं उपस्थित हों तो उनके प्रतिनिधि के लिए अलग VIP प्रोटोकॉल का कोई कानूनी आधार नहीं बनता।

प्रशासनिक दृष्टिकोण- प्रशासन का तर्क सरल था सुरक्षा और प्रमुख पद है, उन्हें मंचोपस्थान मिलना चाहिए- और मिला भी, परंतु मंत्री स्तर की पार्किंग और सुरक्षा का अधिकार स्वतः लागू नहीं होता, स्पष्ट शब्दों में-विधायक स्वयं उपस्थित हों तो उनके प्रतिनिधि के लिए अलग VIP प्रोटोकॉल का कोई कानूनी आधार नहीं बनता।

मानसिकता की पड़ताल- यह विवाद नियमों से ज्यादा मानसिकता का प्रतीक है, राजनीति में सम्मान कभी-कभी हवा-पानी जैसा हो जाता है कम मिले तो घुटन होने लगती है, नई पीढ़ी की राजनीति में 'दिखावटी प्रतिष्ठा' का आकर्षण बढ़ा है, गाड़ी, बोर्ड, काफिला-ये सब पद का प्रतीक बन जाते हैं, लेकिन क्या लोकतंत्र का मूल भाव यही है? जनता की प्रतिक्रिया- स्थानीय लोगों से बातचीत में मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आईं नेता व नेताइन जी पैदल आ जाते तो क्या बिगड़ जाता? जनता के बीच चलना अपमान नहीं, उदाहरण होता, नियम सबके लिए समान हों, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा, कुछ समर्थकों ने इसे 'आत्मसम्मान' का मुद्दा बताया, पर बहुसंख्यक मत सादगी के पक्ष में दिखता।

अमृतधारा का प्रतीकात्मक संदेश- अमृतधारा जलप्रपात ऊंचाई से गिरता है, पर गिरकर भी शीतल रहता है, राजनीति में भी ऊंचाई मिलना स्वाभाविक है, पर यदि विनम्रता गिर जाए, तो विवाद की धारा तेज हो जाती है।

व्यंग्य की परत- इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा व्यंग्य यही है जिस भीड़ ने नेता को खास बनाया, उसी भीड़ के बीच चलने में हिचक क्यों? क्या गाड़ी की दूरी ही सम्मान की गारंटी है? क्या नेम प्लेट के बिना पहचान कम हो जाती है? लोकतंत्र में असली वही आईपी वह है, जो बिना बोर्ड के भी पहचाना जाए।

-रवि सिंह-

एमसीबी/मनंदरागढ़, 16 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

प्रकृति की गोद में बसे अमृतधारा जलप्रपात का नाम सुनते ही मन में शीतलता, हरियाली और जलधारा की मधुर ध्वनि गुंजती है, लेकिन इस वर्ष आयोजित अमृतधारा महोत्सव में जलधारा से ज्यादा गरम थी राजनीति की धारा, जिला मनंदरागढ़-चिरमिरी-भरतपुर के इस प्रतिष्ठित आयोजन में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ, जिसने सांस्कृतिक उत्सव को प्रोटोकॉल बनाम प्रतिष्ठा की बहस में बदल दिया, यह रिपोर्ट केवल एक पार्किंग

पृष्ठभूमि: उत्सव का उद्देश्य और राजनीतिक उपस्थिति

अमृतधारा महोत्सव जिले की सांस्कृतिक पहचान बन चुका है, लोकनृत्य, आदिवासी संस्कृति, पारंपरिक कला और जनभागीदारी इसका मूल स्वर है, इस बार कार्यक्रम में कई विशिष्ट अतिथि आमंत्रित थे, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सहित अन्य मंत्रालय मंचासीन थे, कैबिनेट मंत्री होने के नाते उन्हें शासन द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल प्राप्त था-जिसमें सुरक्षा, निर्धारित व्हीआईपी पार्किंग और काफिला प्रवेश शामिल है, यहीं से कहानी की दिशा बदलती है।

विवाद का विवरण नहीं है, बल्कि उस मानसिकता की पड़ताल है जो लोकतंत्र में पद और पहचान के बीच संतुलन खो देती है।

बता दे की प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर अमृतधारा जलप्रपात के नाम पर आयोजित अमृतधारा महोत्सव इस बार सांस्कृतिक रंगों से कम और राजनीतिक तमतमाहट से ज्यादा चर्चित रहा, जिला मनंदरागढ़-चिरमिरी-भरतपुर में हुए इस आयोजन में जहां एक ओर लोकनृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ चल रही थीं, वहीं दूसरी ओर मंच के बाहर 'प्रोटोकॉल' और 'प्रतिष्ठा' की अलग ही पटकथा लिखी जा रही थी।

सम्मान बनाम सुविधा: फर्क कितना ?

मंच पर स्थान सुनिश्चित था, उद्घोषणा में नाम शामिल था, औपचारिक सम्मान तय था, लेकिन सवाल यह उठ खड़ा हुआ कि क्या सम्मान की पूर्णता तभी है जब गाड़ी मंच के समीप पहुंचे? कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गाड़ी रोके जाने पर नाराजगी व्यक्त की गई, प्रशासनिक अधिकारियों को तीखी बातें सुनाई गईं, नेम प्लेट हटाकर फेंकने की घटना भी चर्चा में आई, अंततः कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया गया, अब प्रश्न यह है क्या पैदल चलना पद की गरिमा के विरुद्ध है?

**असली सम्मान कहाँ ? अमृतधारा
महोत्सव का यह विवाद हमें तीन
बातें सिखाता है...**

**प्रोटोकॉल नियमों से चलता है,
भावनाओं से नहीं।**

**पद की गरिमा सादगी से बढ़ती है, दूरी
से नहीं। लोकतंत्र में जनता से दूरी नहीं,
निकटता सम्मान दिलाती है...**

जब गाड़ी बनी गरिमा का प्रतीक

मामला सीधा-सा था-मुख्य अतिथियों के लिए निर्धारित पार्किंग में एक वाहन को प्रवेश नहीं मिला, वाहन पर नगर पालिका अध्यक्ष का बोर्ड लगा था, साथ में विधायक प्रतिनिधि भी थे, प्रशासन ने सुरक्षा कारणों और तय प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए गाड़ी रोक दी, बस...यहीं से सम्मान की गाड़ी भावनाओं की भीड़ में फंस गई, कहते हैं लोकतंत्र में नेता जनता के बीच से निकलकर आते हैं, लेकिन यहाँ सवाल यह खड़ा हो गया- क्या नेता जनता के बीच चल भी सकते हैं?



विवाद की शुरुआत: गाड़ी और गेट

कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा कारणों से बैरिकेडिंग की गई थी, मुख्य अतिथियों के लिए अलग पार्किंग स्थल निर्धारित था, सूत्रों के अनुसार, नगर पालिका अध्यक्ष की गाड़ी-जिसमें विधायक प्रतिनिधि भी मौजूद थे-मुख्य पार्किंग तक ले जाने का प्रयास किया गया। वाहन पर पद का बोर्ड लगा था, प्रशासन ने सूची देखी, नाम मंच पर था, पर पार्किंग सूची में नहीं, गाड़ी रोक दी गई, और यहीं से शुरू हुई 'सम्मान' की परिभाषा पर बहस।

अंततः प्रश्न वही है

**सम्मान की भूख नेताजी
को थी या उनकी गाड़ी
को ? अमृतधारा की
शीतलता शायद यही
संदेश देती है, ऊंचाई
पाकर भी विनम्र रहना
ही असली राजनीति है...**

ऑडिटोरियम में श्रमिक जन संवाद सम्मेलन का आयोजन

राज्य सरकार की प्रतिबद्धता श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना: मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े

विधायक एवं अन्य वक्ताओं के विचार

प्रतापपुर विधायक शकुंतला पोते ने कहा कि ऐसे संवाद कार्यक्रम शासन और श्रमिकों के बीच की दूरी को कम करने का माध्यम हैं, जिससे योजनाओं का लाभ सीधे पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे, श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष योगेश दत्त मिश्रा ने श्रमिकों से श्रम विभाग की योजनाओं से जुड़ने का आह्वान किया, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

ये रहे उपस्थिति...

कार्यक्रम में पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व अध्यक्ष भीमसेन अग्रवाल, सूरजपुर के अध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल, श्री मुरली मनोहर सोनी, श्री संदीप अग्रवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे, जिला कलेक्टर एस. जयवर्धन, श्रम अधिकारी श्री एलेन मिंज तथा संबंधित विभागीय अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद थे।

-संवाददाता-
सूरजपुर, 16 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

तिलसिंवा स्थित सूरजपुर ऑडिटोरियम में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के मुख्य आतिथ्य में श्रमिक जन संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रमिक बंधु, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

इस अवसर पर श्रम विभाग द्वारा उपस्थित श्रमिकों को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई, ताकि पात्र हितग्राही योजनाओं से जुड़कर लाभान्वित हो सकें, कार्यक्रम के दौरान जिले के 2539 हितग्राहियों को कुल 99 लाख 66 हजार 627 रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई। साथ ही मिनिमहतारी जतन योजना, सियान योजना एवं नोनिहाल छात्रवृत्ति



योजना के डेमो चेक का वितरण भी किया गया, मंच पर आयोजित जनसंवाद सत्र में श्री योगेश कुमार एवं श्री राजकुमार सहित हितग्राहियों ने मानिकपुरी, श्रीमती दुलेश्वरी, सुश्री यात्री अपने अनुभव साझा किए।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े का संबोधन

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि श्रमिक जन संवाद सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और दिहाड़ी मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा एवं आर्थिक सहायता से जोड़ना है, उन्होंने कहा, यह केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि शासन और श्रमिकों के बीच सीधे संवाद का सशक्त माध्यम है। राज्य सरकार श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, उन्होंने श्रमिकों को मेहनतकश वर्ग की रीढ़ बताते हुए उनका सम्मान भी किया।

सांसद का उद्बोधन

सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने कहा कि श्रमिक प्रदेश की इमारत खड़ी करते हैं, सड़कें हों, भवन हों, पुल हों या कोई भी निर्माण कार्य-हर जगह श्रमिकों का अमूल्य योगदान है, उनकी मेहनत के बिना विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती, उन्होंने श्रमिकों की भूमिका को विकास की आधारशिला बताया।

मौत का मेडिकल माफिया! इंदौर से छत्तीसगढ़ तक नकली दवाइयों का जाल, ट्रांसपोर्ट की आड़ में खेला जा रहा था जिंदगी से खेल?

रायपुर/भाटापारा/रायगढ़/इंदौर,
16 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

यह कोई साधारण आर्थिक अपराध नहीं... यह सीधा-सीधा जिंदगी पर हमला है, छत्तीसगढ़ में नकली दवाइयों का ऐसा कथित नेटवर्क सामने आया है, जिसे जानकार 'मौत का मेडिकल माफिया' कहने लगे हैं, सूत्रों के अनुसार, इंदौर से दवाइयों की सप्लाई कर उन्हें असली बताकर छत्तीसगढ़ के बाजारों में उतारा जा रहा था, पैकेजिंग चमकदार, रैपर भरोसेमंद, एमआरपी प्रिंटेड-सब कुछ सही, लेकिन अंदर की गोलियाँ... क्या वे सचमुच वही थीं जो लिखी गई थीं? यह रिपोर्ट उपलब्ध दस्तावेजों, ट्रांसपोर्ट रिकॉर्ड, सूत्रों और प्राथमिक जांच सूचनाओं पर आधारित है, अंतिम सत्य आधिकारिक लेब रिपोर्ट और न्यायिक प्रक्रिया से स्पष्ट होगा, लेकिन एक बात साफ है- अगर यह नेटवर्क सच है, तो छत्तीसगढ़ को अब उदाहरण पेश करने वाली सख्त कार्रवाई की जरूरत है।

'गोल्डन' रस्ता या काला खेल?

सूत्रों का दावा है कि इंदौर स्थित माँ बीजासेन ट्रेडिंग से माल बुक होता था, परिवहन के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल होता था - नागपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट, गंतव्य? भाटापारा की प्रेम प्रकाश एजेंसी व सारंगढ़ की सरस्वती मेडिकोज दवा यह भी है कि यह सिलसिला एक-दो महीने नहीं, बल्कि पिछले लगभग पांच वर्षों से चल रहा था।

मुनाफा बनाम मानव जीवन

अगर आरोप सही हैं, तो यह सिर्फ माफिया नहीं - यह 'सॉलेंट किलिंग सिंडिकेट' है, नकली दवा सिर्फ पैसा नहीं कमाती-यह इलाज मारती है, यह भरोसा मारती है, और कभी-कभी... इंसान भी।

सालाई चैन या संरक्षण चैन?

दस्तावेजी रिकॉर्ड और ट्रांसपोर्ट एंटी यह संकेत देते हैं कि दवाइयों की खेप नियमित अंतराल पर भेजी गई, सवाल यह है-अगर यह सच अवैध था, तो इतने लंबे समय तक बिना बाधा कैसे चलता रहा? खोजी सूत्रों का दावा है कि यह नेटवर्क केवल

असली जैसा रैपर, अंदर 'खाली इलाज'?

खोजी सूत्र बताते हैं की दवाइयां कम कीमत पर उठाई जाती थीं, बाजार में एमआरपी पर बेची जाती थीं, मुनाफा कई गुना, लेकिन अगर सक्रिय तत्व ही न हो, तो दवा इलाज नहीं - धोखा बन जाती है, एंटीबायोटिक अगर बेअसर हो, तो संक्रमण बढ़ता है, गंभीर बीमारी की दवा अगर नकली हो, तो मरीज का भरोसा ही नहीं - जान भी दांव पर लग जाती है।

दिसंबर 2025: जब पहली बार पर्दा हटा

दिसंबर 2025 में कथित तौर पर बड़ी खेप पकड़ी गई, नमूने जब्त हुए, जांच शुरू हुई, लेकिन सवाल यह है, क्या यह नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने की कार्रवाई थी या सिर्फ एक सतही कदम? कुछ सूत्रों का आरोप है कि इस कारोबार को वर्षों से राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा, हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, चौकाने वाली बात यह कि जानकार इसे 'सिस्टम के भीतर सिस्टम' बताते हैं - जहां बिना संरक्षण के इतने बड़े पैमाने पर सप्लाई संभव नहीं।

कारोबारी समझ का परिणाम नहीं था, बल्कि 'ऊपर तक' संपर्कों के सहारे संचालित हो रहा था, हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जानकार मानते हैं कि बिना प्रशासनिक या राजनीतिक ढाल के इतने बड़े पैमाने पर जोखिम भरा कारोबार टिक पाना कठिन होता है।

असली पैकेजिंग, संदिग्ध कंटेनर?

सूत्रों के मुताबिक: दवाइयां ब्रांडेड रैपर में आती थीं, बैच नंबर, एमआरपी, मैनुफैक्चरिंग डिटेल्स-सब कुछ मानक जैसा, लेकिन आरोप है कि अंदर की गुणवत्ता संदिग्ध थी, यदि सक्रिय तत्व मानक के अनुरूप न हों, तो दवा इलाज नहीं, धम बन जाती है, और यही धम सबसे खतरनाक है-क्योंकि मरीज, डॉक्टर और परिवार-सभी को भरोसा रहता है कि इलाज हो रहा है।

कार्रवाई और उसके बाद की चुपड़ी

दिसंबर 2025 में कथित तौर पर बड़ी मात्रा में दवाइयां पकड़ी गईं, नमूने लेब भेजे गए, लेकिन उसके बाद सार्वजनिक डोमेन में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई, यही से 'सिस्टम के भीतर सिस्टम' की चर्चा तेज हुई, कुछ सूत्रों का कहना है कि कार्रवाई की दिशा और दायरा सीमित

रखने का प्रयास हुआ, हालांकि यह दावा भी जांच का विषय है।

अब स्वास्थ्य मंत्री को खुद संभालनी होगी कमान

छत्तीसगढ़ में यदि नकली या संदिग्ध दवाइयों का नेटवर्क सक्रिय होने के आरोप सामने आ रहे हैं, तो यह केवल प्रशासनिक स्तर का मामला नहीं है-यह सीधे तौर पर जनस्वास्थ्य से जुड़ा प्रश्न है, दवा सिर्फ व्यापारिक वस्तु नहीं होती, यह जीवन और मृत्यु के बीच खड़ी अंतिम उम्मीद होती है, ऐसे में यदि दवाइयों की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं, तो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की भूमिका स्वतः महत्वपूर्ण हो जाती है।

वर्षों जरूरी है मंत्री स्तर की देखल?

- **जनविश्वास बहाल करना**-जब लोगों को संदेह होने लगे कि बाजार में बिक रही दवा असली है या नहीं, तो स्वास्थ्य व्यवस्था की विश्वसनीयता कमजोर पड़ती है। मंत्री का सार्वजनिक हस्तक्षेप भरोसा बहाल कर सकता है।
- **स्वतंत्र जांच की घोषणा**-यदि आरोप गंभीर हैं, तो उच्चस्तरीय या न्यायिक जांच का आदेश दिया जाना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की राजनीतिक या प्रशासनिक हस्तक्षेप की आशंका खत्म हो।

कैसे फैलता है जड़? सूत्रों के मुताबिक

1. बड़े डीलर माल लेते हैं।
2. वही माल छोटे मेडिकल स्टोर्स तक जाता है।
3. गांव-कस्बों में दवाइयां पहुंचती हैं।
4. डॉक्टर पर्चा लिखता है।
5. मरीज भरोसे से दवा खरीदता है, और यहीं से शुरू होता है असली खतरा, इलाज की जगह मिलती है सिर्फ उम्मीद का धोखा।

पहले भी उठे थे नाम-

रायपुर के लालपुर क्षेत्र में पहले भी कथित तौर पर 'शिशुपाल' नाम सामने आया था, जिसकी दुकान अब बंद बताई जाती है, लेकिन सवाल वही-क्या चेहरे बदलें हैं या खेल?

अब प्रदेश के सामने बड़े सवाल

- जब्त दवाओं की लेब रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं?
- सप्लाई चैन की वित्तीय जांच कब होगी?
- ट्रांसपोर्ट रिकॉर्ड की फॉरेंसिक ऑडिट होगी या नहीं?
- राजनीतिक संरक्षण के आरोपों की स्वतंत्र जांच कौन करेगा?
- क्या पूरे प्रदेश में मेडिकल दुकानों की घघन जांच होगी?

- **राज्यव्यापी विशेष अभियान** - मेडिकल दुकानों, थोक एजेंसियों और ट्रांसपोर्ट रिकॉर्ड की व्यापक जांच कर स्पष्ट संदेश दिया जा सकता है कि जनस्वास्थ्य से समझौता बर्दाश्त नहीं आरोप गंभीर हैं, तो उच्चस्तरीय या न्यायिक जांच का आदेश दिया जाना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की राजनीतिक या प्रशासनिक हस्तक्षेप की आशंका खत्म हो।
- **लेब रिपोर्ट सार्वजनिक करना** - जब नमूनों की परीक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक करने से पारदर्शिता बढ़ेगी और अफवाहों पर विराम लगेगा।



सवाल सरकार से भी...

यह मुद्दा केवल विपक्ष या सत्ता का नहीं है, यदि यह नेटवर्क वर्षों से सक्रिय रहा, तो इसका मतलब है कि निगरानी तंत्र में कहीं न कहीं कमजोरी रही है, ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री के सामने दोहरी जिम्मेदारी है, वर्तमान में चल रहे किसी भी अवैध नेटवर्क को रोकना और भविष्य के लिए ऐसी प्रणाली विकसित करना जो नकली दवाइयों को बाजार तक पहुंचने से रोक दे, यदि दोषी पाए जाते हैं, तो केवल लाइसेंस रद्द करना पर्याप्त नहीं होगा, उदाहरणार्थक दंड और आपराधिक कार्रवाई ही भविष्य में ऐसे गिरोहों को हतोत्साहित कर सकती है।

क्या यह राजनीति से परे है?

सूत्रों का आरोप है कि यह नेटवर्क किसी एक दल या एक सरकार तक सीमित नहीं रहा, वर्षों से अलग-अलग दौरे में संरक्षण के सहारे काम चलता रहा, यह आरोप गंभीर है, और यदि इनमें सच्चाई है, तो यह केवल आपराधिक मामला नहीं, बल्कि संस्थागत विफलता का संकेत है।

जांव क्यों मुश्किल?

नेटवर्क में जुड़े लोग सामने नहीं आते, अंदरूनी सूचना (टिप-ऑफ) मिलना दुर्लभ होता है, वित्तीय लूट-देन कई स्तरों पर विभाजित रहता है, छोटे डीलर अनजाने में भी सप्लाई चैन का हिस्सा बन सकते हैं, यही वजह है कि 'सिस्टम के भीतर सिस्टम' लंबे समय तक छिपा रहता है।

मानसिक रोगी बेटे ने किया खून, पैसे नहीं मिलने पर पिता के टुकड़े-टुकड़े कर दिए

बिलासपुर, 16 फरवरी 2026।

पैसों के लालच में बेटा ही अपने बुजुर्ग पिता की मौत का कारण बन गया। सिरिगुडी थाना इलाके के मनखोल में सोमवार को आरोपी बेटे नीतू धुव ने अपने पिता की नृशंस हत्या कर दी। सनकी बेटे ने हत्या के बाद शव के कई टुकड़े भी किए। पूरे फर्श पर खून बिखर गया। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार, नीतू धुव नामक 40 वर्षीय व्यक्ति ने अपने 70 वर्षीय पिता मनारखन धुव को फावड़े से वार कर हत्या कर दी। आरोपी पुत्र नशे का आदी बताया जा रहा है। उसने अपने पिता से पैसों की मांग की थी। जब पिता ने पैसे देने से इनकार किया तो गुस्से में आकर उसने फावड़े से तांबड़ोड़ हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से पिता की मौत पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। घटना की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इधर परिवार में मायम पसर गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में घरेलू विवाद और नशे की लत घटना की मुख्य वजह सामने आ रही है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।



एक्सीडेंट में बेटे को खोने के बाद माता-पिता ने किया सुसाइड

जांजीर-चांपा, 16 फरवरी 2026।

जिले से एक हृदयविकारक घटना सामने आई है। इकलौते बेटे के मौत के सदमे में उसके माता-पिता ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। सोमवार को घर में पेड़ पर दोनों की एक साथ फंदे पर लटक शव मिला। मुक्तकों की पहचान रमाबाई पटेल (47) और कृष्णा पटेल (48) घटना से इलाके में शोक व्याप्त हो गया। मामला शिवरीनारायण थाना के धरदई गांव का है। जानकारी की मुताबिक, कुछ दिन पहले ही दंपति के इकलौते बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि बेटे की असमय मृत्यु से दंपति गहरे सदमे में थे। शुरुआती जांच में मानसिक आघात के चलते आत्मघाती कदम उठाने की बात सामने आ रही है। सोमवार सुबह दोनों की पेड़ के फंदे पर लटकी लाश मिलने की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को सुरक्षित नीचे उतार लिया। पंचनामा तैयार कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।



बस्तर में संघर्ष की आग से समृद्धि के उजाले तक : बृजमोहन अग्रवाल

रायपुर, 16 फरवरी 2026। राजधानी रायपुर में आयोजित एक महत्वपूर्ण परिचर्चा में नक्सलवाद और बस्तर के विकास जैसे अहम विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। कार्यक्रम का आयोजन दैनिक लोकमाया के 16वें स्थापना दिवस के अवसर पर किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। परिचर्चा का विषय 'बस्तर का विकास - नक्सलवाद का अंत' रखा गया, जिसने राज्य की मौजूदा परिस्थितियों और विकास की दिशा को लेकर सार्थक विमर्श का मंच प्रदान किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने अपने विचार रखते हुए कहा कि नक्सलवाद किसी सामाजिक या आर्थिक आंदोलन का स्वरूप नहीं रहा, बल्कि यह विकास-विरोधी 'भय का तंत्र' बनकर उभरा।

संयुक्त मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति बैठक सम्पन्न....

हमारा लक्ष्य वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' की संकल्पना को पूरा करना है : मुख्यमंत्री साय

रायपुर, 16 फरवरी 2026।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों के प्रदेश से लेकर बृहत् स्तर तक पदाधिकारी व कार्यकर्ता शासन की योजनाओं और 'मोदी की गारंटी' की सफलताओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए सक्रिय हों। हमारा लक्ष्य वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' की संकल्पना को पूरा करना है। सच्ची सेवा भावना के साथ हमें एक शक्तिशाली और समृद्धशाली भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभानी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री साय ने सोमवार को राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यलय में संयुक्त बैठक की प्रदेश कार्यसमिति बैठक को संबोधित करते हुए सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी और कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जिसके देशभर में 14 करोड़ कार्यकर्ता और प्रदेश में 60 लाख सदस्य व 80 हजार सक्रिय कार्यकर्ता हैं। युवा, महिला, किसान, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक मोर्चों के



माध्यम से समाज के हर वर्ग तक पहुंचना हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमने मात्र दो वर्षों में मोदी की गारंटी के अधिकांश वादों को पूरा कर दिया है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति दी। आज हर पंचायत में औसतन 300 मकान बन रहे हैं और 10 लाख से ज्यादा परिवारों का गृह प्रवेश हो चुका है। छत्तीसगढ़ में 21 किंवदंत प्रति एकड़ धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति किंवदंत की

दर से की जा रही है। होली के पहले 25.24 लाख किसानों के खातों में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की अंतर राशि जमा की जाएगी। इसी प्रकार महिला सशक्तीकरण के दृष्टिगत 'महारी वंदन योजना' के तहत 70 लाख से अधिक माताओं को प्रति माह 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। तैदूपता संग्राहकों को 5500 रुपए पारिश्रमिक, भूमिहीन कृषकों को 10 हजार रुपए सालाना दिए जा रहे हैं।

सुरक्षाबलों को नक्सल मोर्चे पर मिली बड़ी सफलता पहाड़ी में छिपाकर रखा गया हथियारों का डंप किया बरामद, बड़ी साजिश नाकाम

गरियाबंद, 16 फरवरी 2026। जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जिला पुलिस बल की ई-30 ऑप्स टीम ने सघन तलाशी अभियान चलाकर थाना मैनपुर क्षेत्र के ग्राम बड़ेगोबरा स्थित सातमारी पहाड़ी में छिपाकर रखे गए नक्सलियों के हथियारों का डंप बरामद किया है, जिनमें 2 एसएलआर, 1 इंसाम राइफल, 1 बारह बोर बंदूक, एसएलआर और इंसाम की मैगजिन और जिंदा कारतूस शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, जनवरी 2026 में गरियाबंद में आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से पूछताछ के दौरान यह अहम जानकारी सामने आई थी। पूछताछ में खुलासा हुआ कि सीपीआई माओवादी की ओडिशा राज्य कमेटी के शीर्ष नेतृत्व ने सातमारी पहाड़ी क्षेत्र में ऑटोमैटिक हथियारों का जखीरा डम्प कर रखा है, जिसका उपयोग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए किया जा सकता था। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। 16 फरवरी 2026 को जिला मुख्यालय से ई-30 ऑप्स टीम को मौके पर रवाना किया गया।



24 फरवरी को आएगा बजट, युवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगा फोकस

रायपुर, 16 फरवरी 2026।

छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार अपने कार्यक्रमाल का एक और महत्वपूर्ण बजट पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का आगामी बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा। सत्र के दूसरे दिन, यानी 24 फरवरी को राज्य का वार्षिक बजट सदन की पटल पर रखा जाएगा। 'ज्ञान-गति' थीम की सफलता के बाद, इस बार भी बजट को एक नई और प्रभावशाली थीम के साथ पेश करने की तैयारी है, जो राज्य के विजन को दर्शाएगी।

महिला, युवा और किसानों के इंट-मिड केन्द्रित होगा बजट

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट की रूपरेखा साझा करते हुए कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाना है। इस बार के बजट में विशेष रूप से महिलाओं, युवाओं और किसानों के कल्याण के लिए बड़ी



योजनाओं की घोषणा हो सकती है। सरकार की प्राथमिकता जनहितकारी योजनाओं को अधिक का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए है। वित्त मंत्री के अनुसार, यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करने वाला 'रोडमैप' साबित होगा।

इस सत्र में कुल 15 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र के पहले दिन राज्यपाल रमेश देका सदन को संबोधित करेंगे। अपने अभिभाषण में राज्यपाल सरकार की अब तक की उपलब्धियों, आगामी नीतियों और राज्य के विकास के लिए निर्धारित लक्ष्यों का विवरण प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्यय पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास को मिलेगी नई रफ्तार : सूत्रों के अनुसार, आगामी बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। राज्य के छोटे और मध्यम शहरों के कार्यालय के लिए सरकार 'रिंग रोड' बनाने की योजना पर काम कर रही है। प्रदेश की बड़ी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में सुगम यातायात के लिए रिंग रोड निर्माण हेतु लगभग 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा सकता है। इसके अलावा, नवा रायपुर स्थित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में छत्तीसगढ़ के गौरव शहीद वीर नारायण सिंह की भव्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया है।